INTERNATIONAL JOURNAL OF HISTORY

E-ISSN: 2706-9117
P-ISSN: 2706-9109
Impact Factor (RJIF): 5.63
www.historyjournal.net
IJH 2026; 8(2): 01-06
Received: 06-11-2025
Accepted: 09-12-2025

Dr. Sandeep Kumar
Department of History, Jay Prakash University Chapra, Bihar, India

Corresponding Author:
Dr. Sandeep Kumar
Department of History, Jay Prakash University Chapra, Bihar, India

औपनिवेशिक भारत में धन की निकासी का सिद्धांत: दादाभाई नौरोजी के योगदानों का मूल्यांकन

Dr. Sandeep Kumar

DOI: https://www.doi.org/10.22271/27069109.2026.v8.i2a.633

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत से ब्रिटेन की ओर होने वाले आर्थिक संसाधनों के एकतरफा प्रवाह, जिसे 'धन की निकासी' कहा जाता है, का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है। इस सिद्धांत के प्रणेता दादाभाई नौरोजी ने अपनी कालजयी कृति 'पावर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया' के माध्यम से यह सिद्ध किया कि भारत की निर्धनता का मूल कारण ब्रिटिश शोषणकारी नीतियां थीं। इस शोध का मुख्य उद्देश्य नौरोजी द्वारा प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियों और उनके द्वारा चिन्हित निकासी के विभिन्न माध्यमों, जैसे-होम चार्जेस, सैन्य व्यय और व्यापारिक असमानता का मूल्यांकन करना है। शोध पत्र इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे नौरोजी ने पहली बार प्रति व्यक्ति आय की गणना करके ब्रिटिश "सुशासन" के दावों को चुनौती दी। निष्कर्षतः, यह पत्र स्पष्ट करता है कि नौरोजी का यह सिद्धांत न केवल एक आर्थिक विश्लेषण था, बल्कि इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक ठोस वैचारिक और आर्थिक आधार प्रदान किया, जिससे जनता में ब्रिटिश राज के प्रति असंतोष और स्वराज्य की चेतना जागृत हुई।

शब्द-कुंजी : धन निकासी, दादाभाई नौरोजी, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, होम चार्जेस, आर्थिक राष्ट्रवाद, प्रति व्यक्ति आय।

प्रस्तावना

19 वीं शताब्दी का उत्तरार्ध भारतीय आर्थिक इतिहास में एक संक्रमण काल के रूप में देखा जाता है। यह वह समय था जब एक तरफ ब्रिटिश प्रशासन भारत में रेलवे, डाक-तार और आधुनिक शिक्षा के माध्यम से 'सभ्य बनाने के मिशन' (Civilizing Mission) का दावा कर रहा था, तो दूसरी ओर भारत की ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था अत्यंत तीव्र गति से क्षय की ओर अग्रसर थी। इस विरोधाभास को समझने और उसे बौद्धिक चुनौती देने का कार्य जिस विद्वान ने सबसे पहले और सबसे सशक्त रूप से किया, वे दादाभाई नौरोजी थे। उन्होंने अपने 'धन की निकासी' के सिद्धांत के माध्यम से ब्रिटिश शासन के उस 'परोपकारी' मुखौटे को उतार दिया, जिसके पीछे गहरा आर्थिक शोषण छिपा था।

औपनिवेशिक भारत में धन की निकासी की अवधारणा केवल एक आर्थिक सिद्धांत मात्र नहीं थी, बल्कि यह भारतीय राष्ट्रवाद के उदय की पहली व्यवस्थित बौद्धिक अभिव्यक्ति थी। इग्नू (IGNOU, EHI-01) के अनुसार, "धन की निकासी का अर्थ भारत के राष्ट्रीय उत्पाद के उस हिस्से से था जो जनता के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था, बल्कि जिसका प्रवाह बिना किसी प्रतिफल के ब्रिटेन की ओर हो रहा था।" नौरोजी ने तर्क दिया कि भारत गरीब इसलिए नहीं था कि यहाँ संसाधनों कमी थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि यहाँ का अधिशेष (Surplus) कृत्रिम रूप से बाहर भेजा जा रहा था।

ऐतिहासिक रूप से, भारत की गरीबी को ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा अक्सर 'अति-जनसंख्या' या 'भारतीयों के आलस्य' का परिणाम बताया जाता था। एनसीईआरटी (कक्षा 12, आधुनिक भारत) के अनुसार, दादाभाई नौरोजी ने इन दावों का खंडन करते हुए यह स्पष्ट किया कि भारत का रक्त निरंतर रूप से 'चूसा' जा रहा है। उन्होंने अपनी प्रमुख कृति Poverty and Un-British Rule in India में 'अन-ब्रिटिश' (अ-ब्रिटिश) शब्द का प्रयोग विशेष रूप से यह दर्शाने के लिए किया कि ब्रिटिश शासन का भारत में व्यवहार स्वयं ब्रिटेन के लोकतांत्रिक मूल्यों और न्यायप्रियता के विपरीत था।

नौरोजी के शोध सबसे बड़ी विशेषता उनकी सांख्यिकीय पद्धति थी। उन्होंने 1867-68 के आंकड़ों का विश्लेषण कर यह निष्कर्ष निकाला कि भारत प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपये वार्षिक थी, जबकि निर्वाह के लिए न्यूनतम व्यय कहीं अधिक था। बिपिन चंद्र (2009) के अनुसार, "नौरोजी ने यह स्थापित किया कि भारत गरीबी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि मानव-निर्मित (मैन-मेड) थी, जो औपनिवेशिक नीतियों का परिणाम थी।"

इस शोध पत्र का उद्देश्य नौरोजी के आर्थिक राष्ट्रवाद के उन आयामों का मूल्यांकन करना है, जिन्होंने भारतीय मानस को यह सोचने पर मजबूर किया कि जब तक धन का यह प्रवाह नहीं रुकता, तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। यह प्रस्तावना इसी वैचारिक यात्रा की भूमिका तैयार करती है, जहाँ आर्थिक आंकड़ों ने राजनीतिक चेतना को जन्म दिया।

धन की निकासी का सिद्धांत: अवधारणा और तंत्र (The Concept and Mechanism of Drain of Wealth)

दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित 'धन की निकासी' का सिद्धांत केवल एक आर्थिक शब्दावली नहीं थी, बल्कि यह ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की 'अन्तःशोषक' प्रकृति का विस्तृत विवरण था। नौरोजी ने इसे 'निकासी' (Drain) इसलिए कहा क्योंकि यह भारत से धन का ऐसा बहिर्गमन था जिसके बदले में भारत को न तो कोई भौतिक वस्तु प्राप्त हुई और न ही कोई आर्थिक लाभ।

निकासी की परिभाषा और स्वरूप: इग्नू (IGNOU, EHI-01) के अनुसार, धन निकासी व्याख्या उस अधिशेष के रूप में जा सकती है जो भारत के कुल राष्ट्रीय उत्पाद का हिस्सा था, लेकिन उसे भारत के पूंजी निर्माण (Capital Formation) में निवेश करने के बजाय ब्रिटेन भेज दिया जाता था। नौरोजी ने तर्क दिया कि यदि यह धन भारत में रहता, तो यहाँ निवेश होता और आय के नए स्रोत पैदा होते। उन्होंने इसे "बहिर्गमन का बहिर्गमन" कहा क्योंकि यह भारत की संभावित विकास क्षमता को भी नष्ट कर रहा था।

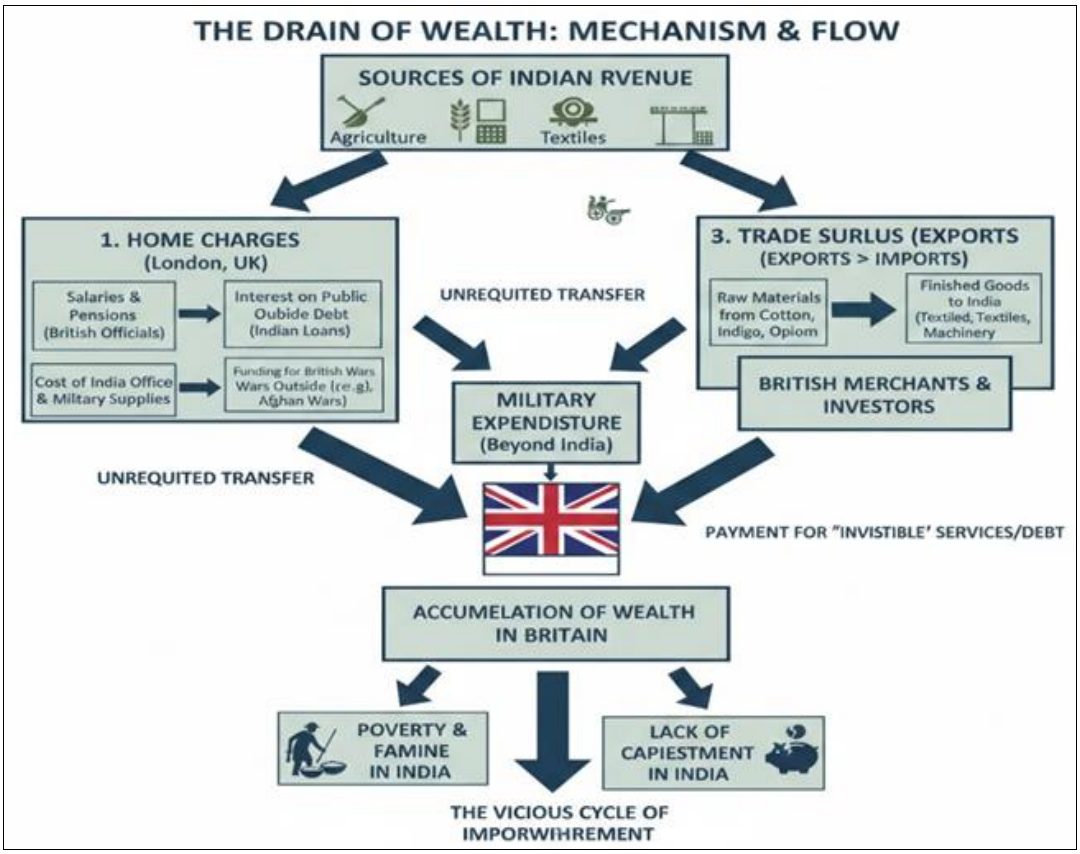

चित्र 1: धन निकासी का प्रवाह और तंत्र

प्रस्तुत चार्ट औपनिवेशिक काल के दौरान भारत से ब्रिटेन की ओर होने वाले आर्थिक संसाधनों के 'एकतरफा हस्तांतरण' (Unrequited Transfer) की प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप से प्रदर्शित करता है। इस प्रवाह तंत्र को निम्नलिखित प्रमुख चरणों में समझा जा सकता है:

राजस्व के स्रोत (Sources of Revenue)

प्रवाह चार्ट के शीर्ष पर स्थित 'भारतीय राजस्व के स्रोत' यह दर्शाते हैं कि निकासी का प्राथमिक आधार भारत की कृषि (Agriculture), पारंपरिक वस्त्र उद्योग (Textiles) और भू-राजस्व प्रणाली थी। भारतीय किसानों और कारीगरों से अधिशेष (Surplus) वसूल कर उसे सरकारी खजाने में जमा किया जाता था।

- **निकासी के तीन मुख्य स्तंभ (The Three Pillars of Drain):** यह चार्ट निकासी को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित करता है, जो दादाभाई नौरोजी के आर्थिक राष्ट्रवाद के मूल स्तंभ हैं:
- **गृह प्रभार (Home Charges):** इसमें लंदन स्थित 'इंडिया ऑफिस' का व्यय, ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन एवं पेंशन, और भारत द्वारा ब्रिटेन से लिए गए ऋणों पर ब्याज शामिल था। यह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा सोख लेता था।
- **सैन्य व्यय (Military Expenditure):** भारतीय सीमाओं से बाहर (जैसे अफगान या बर्मा युद्ध) लड़े गए ब्रिटिश साम्राज्यवादी युद्धों का वित्तीय भार भारतीय राजस्व पर डाला गया, जिसे चार्ट में मध्य भाग में दर्शाया गया है।
- **व्यापार अधिशेष (Trade Surplus):** चार्ट का दायां भाग 'अदृश्य निकासी' को स्पष्ट करता है। भारत से कच्चा माल (कपास, नील, अफीम) तो बाहर जा रहा था, लेकिन उसके बदले प्राप्त होने वाला अधिशेष भारत में निवेश होने के बजाय ब्रिटिश व्यापारियों और निवेशकों के पास 'मुनाफे' के रूप में वापस ब्रिटेन चला जाता था।
- **संचय और परिणाम (Accumulation and Consequences):** चार्ट का निचला हिस्सा इस आर्थिक प्रक्रिया के विनाशकारी परिणामों को रेखांकित करता है:
- **ब्रिटेन में संचय (Accumulation in Britain):** भारतीय धन का उपयोग ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति को वित्तपोषित करने और वहां पूंजी निर्माण के लिए किया गया।
- **भारत में गरीबी और अकाल (Poverty & Famine):** संसाधन के इस निरंतर पलायन ने भारत उत्पादक क्षमता को नष्ट कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप बार-बार अकाल पड़े।
- **पूंजी निवेश का अभाव (Lack of Capital Investment):** चार्ट स्पष्ट करता है कि भारत में 'पूंजी निर्माण' की प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई थी, जिसे नौरोजी ने "दुष्चक्र" (Vicious Cycle of Impoverishment) संज्ञा दी थी।

निष्कर्षतः, यह चित्र स्पष्ट करता है कि भारत की निर्धनता किसी प्राकृतिक आपदा का परिणाम नहीं थी, बल्कि एक सुव्यवस्थित 'आर्थिक ड्रेन' (Economic Drain) का परिणाम थी, जिसने भारत को संसाधनों से विहीन और ब्रिटेन को समृद्ध बनाया

निकासी के मुख्य तंत्र (Mechanism of Drain)

नौरोजी ने उन विशिष्ट माध्यमों की पहचान की जिनके द्वारा भारतीय संसाधनों का दोहन किया जा रहा था। इन माध्यमों को निम्नलिखित उप-शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है:

गृह प्रभार (Home Charges): यह निकासी का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष रूप था। इसमें वे खर्च शामिल थे जो भारत के शासन के नाम पर लंदन में स्थित 'इंडिया ऑफिस' द्वारा किए जाते थे। आर.सी. दत्त (1902) ने अपनी पुस्तक 'The Economic History of India' में स्पष्ट किया है कि 'होम चार्जेस' के नाम पर भारत से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर जा रही थी। इसके मुख्य घटक थे:

- ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरधारकों को दिया जाने वाला लाभांश।
- ब्रिटेन में रहने वाले सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन।
- लंदन में स्थित भारतीय सचिव (Secretary of State) के कार्यालय का रखरखाव।

भारत द्वारा ब्रिटेन से लिए गए सार्वजनिक ऋण पर ब्याज।

सैन्य व्यय और विदेशी युद्ध: ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए लड़े गए युद्धों (जैसे अफगान युद्ध, बर्मा युद्ध) का सारा वित्तीय बोझ भारतीय राजस्व पर डाला गया। बिपिन चंद्र (2010) के अनुसार, "भारतीय सेना का उपयोग ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए किया जाता था, लेकिन उसका वेतन और गोला-बारूद का खर्च भारतीय किसान के लगान से वसूला जाता था।"

व्यापारिक अधिशेष का दुरुपयोग (Unrequited Exports)

औपनिवेशिक आंकड़ों में भारत का निर्यात हमेशा उसके आयात से अधिक दिखाई देता था (Favourable Trade Balance)। सामान्यतः व्यापार अधिशेष किसी भी देश के लिए अच्छा होता है, लेकिन भारत के संदर्भ में यह 'अप्रत्यक्ष निकासी' थी। एनसीईआरटी (कक्षा 12) के अनुसार, भारत से होने वाले इस अतिरिक्त निर्यात का भुगतान सोने या चांदी में होने के बजाय 'होम चार्जेस' के भुगतान में ही कट जाता था।

विदेशी पूंजी निवेश पर लाभ

ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भारत में रेलवे, बागान और बैंकों में निवेश किया था। इस निवेश से होने वाला सारा लाभ और ब्याज वापस ब्रिटेन चला जाता था। नौरोजी ने इसे 'राष्ट्रीय हानि' माना क्योंकि इस पूंजी का लाभ भारतीयों को नहीं मिल रहा था।

निकासी की मात्रा का आकलन

नौरोजी ने अलग-अलग समय पर निकासी की राशि के अलग-अलग अनुमान प्रस्तुत किए। उन्होंने अनुमान लगाया था कि 1835 से 1872 के बीच लगभग 50 करोड़ पाउंड की निकासी हुई थी। ताराचंद (1961) ने 'History of the Freedom Movement in India' में उल्लेख किया है कि यह राशि तत्कालीन भारत की कुल बचत क्षमता से कहीं अधिक थी।

दादाभाई नौरोजी का योगदान और उनकी पद्धति (Naoroji's Contribution and Methodology)

दादाभाई नौरोजी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह था कि उन्होंने आर्थिक राष्ट्रवाद को केवल भावनाओं या नारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे कठोर सांख्यिकीय साक्ष्यों पर आधारित किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि भारत की गरीबी कोई दैवीय संयोग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित आर्थिक नीति का परिणाम है।

सांख्यिकीय पद्धति और प्रति व्यक्ति आय का आकलन

नौरोजी ने 1867-68 के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए एक अभूतपूर्व पद्धति अपनाई। इग्नू (IGNOU, EHI-01) के विश्लेषण के अनुसार, नौरोजी ने कुल कृषि उत्पादन और फिर उसमें एक निश्चित प्रतिशत गैर-कृषि आय जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की।

- **₹20 की गणना:** उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एक औसत भारतीय की वार्षिक आय मात्र 20 रुपये थी।
- **तुलनात्मक विश्लेषण:** उन्होंने इस आंकड़े की तुलना जेल के कैदियों के आहार पर होने वाले खर्च से की। उन्होंने पाया कि ब्रिटिश जेलों में एक कैदी के भरण-पोषण पर वार्षिक 27 से 34 रुपये खर्च होते थे।
- **निष्कर्ष:** नौरोजी ने यह तर्क दिया कि भारत का एक आम नागरिक जेल के अपराधी से भी बदतर जीवन जी रहा था। यह तर्क इतना शक्तिशाली था कि इसने ब्रिटिश संसद तक में खलबली मचा दी थी।

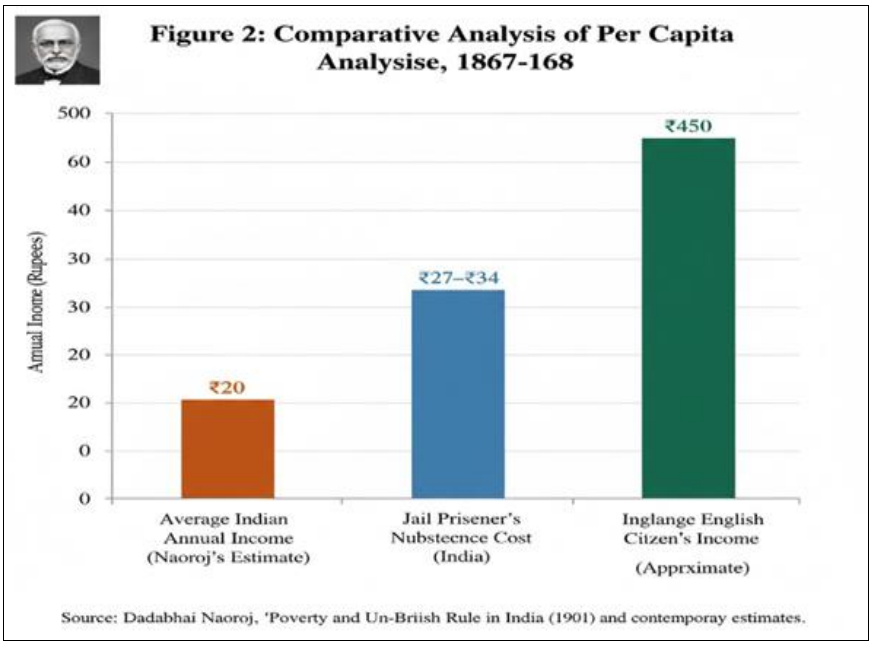

चित्र 2: की व्याख्या: प्रति व्यक्ति आय का तुलनात्मक विश्लेषण (1867-68)

प्रस्तुत चार्ट दादाभाई नौरोजी द्वारा 'राष्ट्रीय आय' की पहली वैज्ञानिक गणना और औपनिवेशिक विषमता को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है:

- **जीवन निर्वाह से कम आय:** चार्ट का सबसे निचला स्तंभ (₹20) यह दर्शाता है कि एक औसत भारतीय की वार्षिक आय अत्यंत न्यून थी। नौरोजी ने इसे सिद्ध करने के लिए जेल के आंकड़ों का उपयोग किया।
- **कैदियों से बदतर स्थिति:** चार्ट स्पष्ट करता है कि ब्रिटिश जेलों में एक अपराधी के भोजन और रखरखाव पर किया जाने वाला न्यूनतम सरकारी खर्च (₹34 तक) एक स्वतंत्र भारतीय नागरिक की औसत आय (₹20) से कहीं अधिक था। यह सिद्ध करता है कि आम जनता कुपोषण और भुखमरी की स्थिति में जी रही थी।
- **औपनिवेशिक आर्थिक खाई:** चार्ट में इंग्लैंड के नागरिक की औसत आय (₹450) और भारतीय आय (₹20) के बीच का विशाल अंतर उस 'आर्थिक दोहन' को उजागर करता है, जिसने भारत को संसाधनों से विहीन कर ब्रिटेन में समृद्धि का अंबार लगाया।
- **निष्कर्ष:** यह विजुअल डेटा प्रमाणित करता है कि भारत की गरीबी कोई 'प्राकृतिक आपदा' नहीं थी, बल्कि यह संसाधनों के निरंतर बहिर्गमन (Drain) का प्रत्यक्ष परिणाम थी।

'पावर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया' (1901)

यह पुस्तक केवल आंकड़ों का संकलन नहीं थी, बल्कि यह ब्रिटिश न्यायप्रियता पर एक करारा प्रहार था। एनसीईआरटी (कक्षा 12) के अनुसार, नौरोजी ने 'अन-ब्रिटिश' (Un-British) शब्द का चयन बहुत सोच-समझकर किया था। वे अंग्रेजों को यह याद दिलाना चाहते थे कि जो शासन वे भारत में चला रहे हैं, वह स्वयं ब्रिटेन के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत (Despotic) है।

'नैतिक निकासी' (Moral Drain) की अवधारणा

नौरोजी का योगदान केवल वित्तीय धन तक सीमित नहीं था। उन्होंने 'नैतिक निकासी' का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। बिपिन चंद्र (2010) के अनुसार, नौरोजी ने तर्क दिया कि:

- उच्च प्रशासनिक पदों से भारतीयों को बाहर रखकर ब्रिटेन भारत के 'प्रशासनिक अनुभव' और 'कौशल' की चोरी कर रहा है।
- जब एक ब्रिटिश अधिकारी भारत में अनुभव प्राप्त कर सेवानिवृत्त होता है, तो वह अपना ज्ञान और अनुभव (Intellectual Capital) वापस ब्रिटेन ले जाता है, जिससे भारत बौद्धिक रूप से भी निर्धन होता जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व

नौरोजी पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश 'हाउस ऑफ कॉमन्स' के सदस्य चुने गए। वहाँ उन्होंने 'वेलबी कमीशन' (Welby Commission, 1895) के सामने भारत का पक्ष रखा। सुमित सरकार (1983) उल्लेख करते हैं कि नौरोजी ने ब्रिटिश सांसदों को यह समझाने में सफलता प्राप्त की कि भारत की गरीबी का मुख्य कारण 'पूंजी की कमी' नहीं, बल्कि 'पूंजी का पलायन' है।

ब्रिटिश दावों का खंडन (Rebuttal of British Claims)

ब्रिटिश राज के समर्थक इतिहासकारों और प्रशासकों (जैसे जॉन स्ट्रेची) का तर्क था कि ब्रिटेन भारत में शांति, कानून का शासन और आधुनिक बुनियादी ढांचा (जैसे रेलवे और सिंचाई) प्रदान कर रहा है, जिसके बदले में लिया जाने वाला धन 'सेवा शुल्क' मात्र है। दादाभाई नौरोजी ने इन दावों का व्यवस्थित और साक्ष्य-आधारित खंडन किया।

रेलवे: विकास या शोषण का माध्यम?

अंग्रेजों ने रेलवे को भारत के लिए 'उपहार' बताया था। इग्नू (IGNOU, EHI-01) के अनुसार, नौरोजी ने तर्क दिया कि रेलवे का निर्माण भारतीय लाभ के लिए

नहीं, बल्कि ब्रिटिश हितों के लिए किया गया था।

- **पूंजी की निकासी:** रेलवे में निवेश की गई ब्रिटिश पूंजी पर 5% गारंटीशुदा ब्याज भारतीय राजस्व से दिया जाता था, चाहे रेलवे मुनाफे में हो या घाटे में।
- **संसाधनों का दोहन:** रेलवे ने भारत के आंतरिक हिस्सों से कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुँचाने और ब्रिटिश निर्मित माल को ग्रामीण बाजारों तक पहुँचाने में मदद की, जिससे स्थानीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश हुआ।

'कानून और व्यवस्था' का मूल्य

ब्रिटिश अधिकारियों का दावा था कि वे भारत को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा और आंतरिक शांति प्रदान कर रहे हैं। बिपिन चंद्र (2010) के अनुसार, नौरोजी ने इसके उत्तर में कहा कि "शान्ति और व्यवस्था तो मिली है, लेकिन वह एक ऐसी शान्ति है जो श्मशान की होती है।" उन्होंने तर्क दिया कि सुरक्षा के नाम पर वसूला गया भारी कर भारत को इतना खोखला कर रहा है कि जनता अकाल और भुखमरी से मर रही है।

विदेशी पूंजी निवेश का भ्रम

ब्रिटिश तर्क था कि वे भारत में पूंजी ला रहे हैं। नौरोजी ने यह सिद्ध किया कि यह 'नई पूंजी' नहीं थी, बल्कि भारत से लूटे गए धन का ही एक हिस्सा था जिसे दोबारा ऋण के रूप में भारत को देकर उस पर ब्याज वसूला जा रहा था। उन्होंने इसे 'पूंजी का चक्रीय दोहन' कहा। आर.सी. दत्त (1902) ने भी इस विचार का समर्थन करते हुए लिखा कि "जब करों का पैसा देश से बाहर जाता है, तो वह खाद के समान है जो भारत के बजाय ब्रिटेन के खेतों को उपजाऊ बना रहा है।"

सुशासन और उच्च वेतन का तर्क

अंग्रेजों ने तर्क दिया कि भारत को एक सक्षम प्रशासनिक सेवा (ICS) दी गई है। नौरोजी ने जवाब दिया कि यदि इन अधिकारियों का वेतन भारतीय औसत आय से सैकड़ों गुना अधिक है और वह वेतन देश से बाहर भेजा जा रहा है, तो यह 'सुशासन' नहीं बल्कि 'आर्थिक रक्तपात' (Bleeding) है।

सिद्धांत का प्रभाव और मूल्यांकन (Impact and Evaluation of the Theory)

दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित 'धन की निकासी' का सिद्धांत केवल एक आर्थिक मॉडल नहीं था, बल्कि इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई वैचारिक और रणनीतिक दिशा प्रदान की। इसका प्रभाव बहुआयामी था, जिसने ब्रिटिश शासन की नैतिकता को बुनियादी तौर पर हिलाकर रख दिया।

- **राजनीतिक और वैचारिक प्रभाव:** नौरोजी के सिद्धांत ने भारतीय राष्ट्रवाद के लिए 'आर्थिक नींव' का कार्य किया। इग्नू (IGNOU, EHI-01) के अनुसार, 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद शुरुआती दो दशकों तक कांग्रेस का पूरा एजेंडा नौरोजी के आर्थिक विचारों से प्रभावित था।
- **स्वराज का आधार:** नौरोजी ने यह सिद्ध किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं, बल्कि आर्थिक दोहन को रोकने का एकमात्र उपाय है। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जब उन्होंने 'स्वराज' की मांग की, तो उसका मुख्य लक्ष्य भारत के धन को भारत में ही रोकना था।
- **जन चेतना:** बिपिन चंद्र (2010) उल्लेख करते हैं कि इस सिद्धांत ने किसानों, मध्यम वर्ग और बुद्धिजीवियों के बीच एक साझा दुश्मन (ब्रिटिश आर्थिक नीतियां) की पहचान की। इसने उस धारणा को तोड़ा कि अंग्रेज भारत के उद्धारक हैं।

सांख्यिकीय और अकादमिक विरासत

नौरोजी ने आधुनिक भारत में 'अनुभवजन्य शोध' (Empirical Research) कीपरंपरा शुरू की। उन्होंने सांख्यिकी का उपयोग एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया। आर.सी. दत्त और जी.वी. जोशी जैसे समकालीन अर्थशास्त्रियों ने नौरोजी के ही पदचिन्हों पर चलते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण किया। एनसीईआरटी (कक्षा 12) के अनुसार, नौरोजी की पद्धति ने बाद में स्वतंत्र भारत में योजना आयोग (Planning Commission) और राष्ट्रीय आय की गणना के लिए एक प्रारंभिक ढांचा प्रदान किया।

अंतरराष्ट्रीय प्रभाव

नौरोजी ने इस सिद्धांत के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश दिया कि भारत की गरीबी उसकी नियति नहीं, बल्कि औपनिवेशिक शासन का परिणाम है। उनके प्रयासों से ही 1895 में 'वेलबी कमीशन' (Welby Commission) का गठन हुआ, जिसमें पहली बार भारतीय राजस्व के व्यय की जांच की गई।

सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन

हालाँकि नौरोजी का सिद्धांत अत्यंत प्रभावशाली था, लेकिन कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने इसकी सीमाओं की ओर भी संकेत किया है:

- **आंतरिक कारकों की उपेक्षा:** आलोचकों का मानना है कि नौरोजी ने अपना पूरा ध्यान 'बाहरी निकासी' पर केंद्रित किया, जबकि भारत की आंतरिक सामाजिक कुरीतियों (जैसे जाति प्रथा, सामंतवाद और तकनीकी पिछड़ापन) की भूमिका को गौण कर दिया।
- **पूंजीवादी दृष्टिकोण:** कुछ मार्क्सवादी इतिहासकारों, जैसे इरफान हबीब (1995) का तर्क है कि नौरोजी का विश्लेषण मुख्य रूप से उभरते हुए भारतीय बुर्जुआ (पूंजीपति वर्ग) के हितों के अनुकूल था।

निष्कर्षत

दादाभाई नौरोजी का 'धन की निकासी' का सिद्धांत भारतीय आर्थिक चिंतन के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। उन्होंने अपनी सांख्यिकीय गणनाओं से यह प्रमाणित कर दिया कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए एक 'परजीवी' की तरह कार्य कर रहा था। नौरोजी ने भारत की निर्धनता का जो वैज्ञानिक कारण प्रस्तुत किया, उसने न केवल अंग्रेजों के 'सभ्य बनाने के मिशन' (Civilizing Mission) के खोखलेपन को उजागर किया, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक ठोस आर्थिक दर्शन भी प्रदान किया। आज भी, विकासशील देशों (Global South) और विकसित देशों के बीच व्यापारिक असंतुलन की चर्चा में नौरोजी का यह सिद्धांत अत्यंत प्रासंगिक बना हुआ है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित 'धन की निकासी' (Drain of Wealth) का सिद्धांत केवल एक आर्थिक तर्क मात्र नहीं था, बल्कि यह औपनिवेशिक शासन की नैतिक और प्रशासनिक वैधता को दी गई सबसे बड़ी बौद्धिक चुनौती थी। नौरोजी ने अपनी पद्धति से यह सिद्ध किया कि भारत की निर्धनता का कारण आंतरिक अक्षमता नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित 'आर्थिक रक्तपात' (Economic Bleeding) था।

नौरोजी के योगदान का मूल्यांकन करते हुए हम निम्नलिखित मुख्य निष्कर्षों पर पहुँचते हैं।

- **वैज्ञानिक आधार:** नौरोजी पहले भारतीय थे जिन्होंने 'डेटा' (Data) को राष्ट्रीयता के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। ₹ 20 प्रति व्यक्ति आय की उनकी गणना ने ब्रिटिश दावों की पोल खोल दी और सांख्यिकी को जन-संवाद का हिस्सा बनाया।
- **उपनिवेशवाद की नई परिभाषा:** उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रिटिश शासन 'अन-ब्रिटिश' (Un-British) था। इसका अर्थ यह था कि अंग्रेज अपने ही देश के लोकतांत्रिक और न्यायप्रिय सिद्धांतों को भारत में लागू नहीं कर रहे थे।

- **राष्ट्रवाद का आर्थिक आधार:** इस सिद्धांत ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती नेतृत्व को एक ठोस आधार दिया। इग्नू (IGNOU, EHI-01) के अनुसार, इसी सिद्धांत ने आगे चलकर 'स्वदेशी' और 'बहिष्कार' जैसे आंदोलनों की वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार की।
- **वैश्विक प्रासंगिक:** नौरोजी का यह सिद्धांत आज भी 'डिपेंडेंसी थ्योरी' (Dependency Theory) और 'ग्लोबल साउथ' के विकास की बहसों में उतना ही प्रासंगिक है, जहाँ विकासशील देशों से संसाधनों का प्रवाह विकसित देशों की ओर निरंतर बना हुआ है।

अंततः, दादाभाई नौरोजी ने न केवल भारत की गरीबी का निदान किया, बल्कि भारतीयों को आत्म-सम्मान और राजनीतिक अधिकार की मांग हेतु एक तार्किक धरातल प्रदान किया। उनका यह कार्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर है, जिसने सिद्ध किया कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. नौरोजी, दादाभाई (1901). Poverty and Un-British Rule in India. लंदन: सननशाइन (Sonnenschein). पृष्ठ संख्या: 1-35, 120-145-प्रति व्यक्ति आय और निकासी के आंकड़ों के लिए।
2. दत्त, आर. सी. (1902). The Economic History of India under Early British Rule. लंदन: केगन पॉल (Kegan Paul). पृष्ठ संख्या: 400-425-होम चार्जेस के विश्लेषण हेतु।
3. इग्नू (IGNOU) (2018). आधुनिक भारत (1857-1964), EHI-01. नई दिल्ली: सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ। इकाई 14, पृष्ठ संख्या: 22-38-आर्थिक राष्ट्रवाद और धन की निकासी।
4. इग्नू (IGNOU) (2020). भारतीय आर्थिक विकास और नीति, BECC-103. नई दिल्ली: अर्थशास्त्र संकाय। इकाई 2, पृष्ठ संख्या: 15-28।
5. एनसीईआरटी (NCERT) (2023). भारतीय इतिहास के कुछ विषय-भाग III, कक्षा 12. नई दिल्ली: प्रकाशन विभाग। अध्याय 10: उपनिवेशवाद और देहात, पृष्ठ संख्या: 257-265।
6. एनसीईआरटी (NCERT) (2021). भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, कक्षा 11. नई दिल्ली: प्रकाशन विभाग। अध्याय 1: स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, पृष्ठ संख्या: 3-12।
7. चंद्र, बिपिन (2010). भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय और विकास (The Rise and Growth of Economic Nationalism in India). नई दिल्ली: हर-आनंद पब्लिकेशन्स। पृष्ठ संख्या: 635-670।
8. चंद्र, बिपिन (2009). आधुनिक भारत का इतिहास. नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान। [पृष्ठ संख्या: 180-195-निकासी सिद्धांत का राजनीतिक प्रभाव]।
9. सरकार, सुमित (1983). आधुनिक भारत: 1885-1947. दिल्ली: मैकमिलन इंडिया। पृष्ठ संख्या: 25-30-मध्यम वर्ग की चेतना और नौरोजी।
10. हबीब, इरफान (2006). भारतीय अर्थव्यवस्था 1858-1914. नई दिल्ली: तुलिका बुक्स। पृष्ठ संख्या: 80-95-कृषि और वाणिज्यिक दोहन।
11. पटेल, दिनयार (2020). Naoroji: Pioneer of Indian Nationalism. कैम्ब्रिज: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। पृष्ठ संख्या: 210-245-नौरोजी की सांख्यिकीय कार्यप्रणाली।
12. मजमुदार, आर. सी. (1963). British Paramountcy and Indian Renaissance, Part II. बॉम्बे: भारतीय विद्या भवन। पृष्ठ संख्या: 1120-1145।
13. ताराचंद (1961). History of the Freedom Movement in India, Vol. II. नई दिल्ली: प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। पृष्ठ संख्या: 320-335।
14. मसानि, आर. पी. (1939). Dadabhai Naoroji: The Grand Old Man of India. लंदन: जॉर्ज एलन एंड अनविन। पृष्ठ संख्या: 45-60।
15. बागची, अमिय कुमार (1972). Private Investment in India, 1900-1939. कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। पृष्ठ संख्या: 150-175।
16. गांगुली, बी. एन. (1965). Dadabhai Naoroji and the Drain Theory. बॉम्बे: एशिया पब्लिशिंग हाउस। [पृष्ठ संख्या: 10-45]।
17. टॉमलिंसन, बी. आर. (1993). The Economy of Modern India, 1860-1970. कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। पृष्ठ संख्या: 32-55।
18. ग्रोवर, बी. एल. एवं मेहता, एस. (2018). आधुनिक भारत का इतिहास-एक नवीन मूल्यांकन. नई दिल्ली: एस. चंद पब्लिशिंग। पृष्ठ संख्या: 345-360।
19. त्रिपाठी, अमलेश (1967). The Extremist Challenge. कलकत्ता: ओरिएंट लॉन्गमैन। पृष्ठ संख्या: 155-168।
20. नंदा, बी. आर. (1977). Gokhale, Gandhi and the Nehrus. लंदन: एलन एंड अनविन। पृष्ठ संख्या: 90-105।